सं. ए-45011/4/2023-समन्वय II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

नई दिल्ली, 17 मई, 2023

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को मार्च माह, 2023 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधरी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 2309- 5054

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6 मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्यमंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (ईए) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, (दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. श्री वी.अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (वित्त)।
14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन/समन्वय/सी एंड सी)
15. सुश्री मनीषा सिन्हा, अपर सचिव (जी 20 लॉजिस्टिक्स (समन्वय-II -2)/ओएमआई/क्रिप्टो आस्ति और सीबीडीसी)
16. आर्थिक कार्य विभाग में सभी प्रभागों के प्रमुख।
    संयुक्त सचिव (आईपीपी/संयुक्त सचिव (आईएसडी)/संयुक्त सचिव (जांच)/संयुक्त सचिव (बजट) संयुक्त सचिव (वित्त मंत्री)/सभी सलाहकार/सीएएए
17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. गार्ड फाइल - 2023

ए-45011/4/2023-समन्वय.II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

विषय: मार्च, 2023 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:

मैक्रोइकॉनॉमिक अवलोकन:

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) के अप्रैल 2023 के अपडेट में वैश्विक वृद्धि दर 2022 के 3.4 प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.8 प्रतिशत और 2024 में मामूली सुधार कर 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। डब्ल्यूईओ के अप्रैल 2023 के अपडेट में भारत को वित्त वर्ष 2024 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पेश किया गया है। वैश्विक विकास की धीमी गति, वैश्वीकरण और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के दबाव के साथ, वैश्विक व्यापार को भी कम किया है। आईएमएफ का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार की मात्रा 2022 में 5.1 प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.4 प्रतिशत हो जाएगी, जो 2024 में थोड़ा सुधरकर 3.5 प्रतिशत हो जाएगी।

वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों में नरमी के साथ व्यापारिक आयात में अधिक तेजी से गिरावट आई। इससे व्यापार घाटा कम हुआ, जिससे भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) दूसरी तिमाही में जीडीपी के 3.7 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में 2.2 प्रतिशत हो गया। निवल सेवा निर्यात में निरंतर वृद्धि और विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषण के मजबूत प्रवाह ने भी चालू खाते के घाटे में सुधार में योगदान दिया।

वित्त वर्ष 2023 में केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय मापदंड भी मजबूत रहे हैं। पूंजीगत व्यय पर केंद्र के जोर ने राज्यों को वित्त वर्ष 2024 के बजट में अपने पूंजीगत व्यय आवंटन में वृद्धि की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। व्यापक आर्थिक गतिविधियों और राजस्व में जोरदार उछाल के कारण राज्यों के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में मजबूती आई है और ज्यादातर राज्यों ने वित्त वर्ष 2024 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3-3.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान जताया है।

मार्च 2023 में मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के साथ आंतरिक व्यापक आर्थिक स्थिरता और मजबूत हुई है, जो खाद्य और मुख्य मुद्रास्फीति में नरमी से प्रेरित है, जो 16 महीने के निचले स्तर पर गिर गई है। मार्च 2023 में सीपीआई-कोर की क्रमिक वृद्धि जून 2022 के बाद सबसे कमजोर है। हालांकि पूरे वित्त वर्ष के लिए सीपीआई वित्त वर्ष 2022 में 5.5 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 6.7 प्रतिशत हो गई, लेकिन वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में यह पहली छमाही में 7.2 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम 6.1 प्रतिशत थी।

महामारी की भयावहता और भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने के बावजूद वित्त वर्ष 2023 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत रहा है। अर्थव्यवस्था में मजबूती 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो प्रवृत्ति दर और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि से अधिक है। बढ़ती व्यापक आर्थिक स्थिरता, जैसे चालू खाते के घाटे में सुधार, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने और नीतिगत दरों में वृद्धि से बचने के लिए पर्याप्त मजबूत बैंकिंग प्रणाली में देखा गया है, ने विकास दर को और सतत् बना दिया है। वित्त वर्ष 2024 में वृद्धि को मैक्रोइकॉनॉमिक चर में और भी मजबूत स्थिरता द्वारा रेखांकित किए जाने की संभावना है।

2. **महत्वपूर्ण विकासः**

(i) वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 परिचालित की गई है।

(ii) भारत को 2024-2026 से तीन साल की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन के लिए दीर्घकालिक वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआई) सह-अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इससे डीपीआई के नेतृत्व वाले वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है।

(iii) माननीय वित्त मंत्री ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया थाः

(क) अमरीकी वाणिज्य मंत्री सुश्री जीना राइमोंडो के साथ द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, नवाचार, आईपीईएफ आदि से संबंधित परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा की गई।

(ख) भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के अवसरों पर विचार-विमर्श के लिए ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री श्री डॉन फैरेल के साथ द्विपक्षीय बैठक।

(iv) इस माह के दौरान जी **20** इंडिया की अध्यक्षता के तहत निम्नलिखित वित्त ट्रैक बैठकें आयोजित की गईं:

(क) भारतीय अध्यक्षता के तहत जी 20 रूपरेखा कार्य समूह (एफडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक 24-25 मार्च, 2023 को चेन्नई में आयोजित की गई थी। इस बैठक के इतर, 25 मार्च, 2023 को 'जलवायु परिवर्तन और मार्ग परिवर्तन का बृहत आर्थिक प्रभाव' नामक जी 20-सीओपी 28 पक्ष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

(ख) भारतीय अध्यक्षता के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह (आईएफए डब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक 30-31 मार्च 2023 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। बैठक के इतर 30 मार्च, 2023 को "एक खंडित दुनिया में वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल (जीएफएसएन) को मजबूत करना" और "सीएएफ समीक्षा सिफारिशों की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) की अपेक्षाओं और एमडीबी की रेटिंग पर संभावित प्रभाव" पर दो सह-कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

(ग) जी 20 सतत वित्त कार्य समूह (एसएफडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक 21-23 मार्च 2023 को उदयपुर में आयोजित की गई थी। एसएफडब्ल्यूजी बैठक के इतर 'एसडीजी के लिए वित्त को सक्षम करना' और 'सतत निवेश का समर्थन करने के लिए गैर-मूल्य नीति लीवर' विषयों पर दो जी-20 कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। इसके

अलावा, जी 20 और सतत वित्त के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए कई जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

(घ) भारतीय अध्यक्षता के तहत अवसंरचना कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक 28-29 मार्च 2023 को विशाखापटनम नम, आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी।

(ङ) वित्तीय समावेशन के लिए द्वितीय जी 20 वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआई) कार्य समूह की बैठक 6-7 मार्च 2023 को हैदराबाद में आयोजित की गई थी। बैठक के इतर, 'वैश्विक दक्षिणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने पर अनुभव और ज्ञान विनिमय कार्यक्रम' 4-6 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। 6 मार्च 2023 को 'वित्तीय समावेशन, तन्यकता, उत्पादकता लाभ और समावेशी विकास के लिए भुगतान प्रणालियों में डिजिटल नवाचारों का उपयोग' पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की गई थी।

(v) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित की गईं में भाग लिया गया:

(क) सचिव (आर्थिक कार्य) ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष लिमिटेड (एनआईआईएफएल) की बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की।

(ख) वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने वित्तीय स्थिरता, एनबीएफआई उत्तोलन और साइबर तन्यकता रिपोर्ट से संबंधित वर्तमान घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए पूर्ण बैठक आयोजित की।

(ग) एनडीबी के अंतरण पर विचार करने के लिए निदेशक मंडल के विशेष बोर्ड की बैठक के लिए एनडीबी निदेशक मंडल की आभासी बैठक हुई।

(घ) एआईआईबी निदेशक मंडल ने सीईआईयू, 2022 वार्षिक वित्तीय विवरण, 2022 पूंजी पर्याप्तता वर्ष-अंत मूल्यांकन, आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एआईआईबी के दृष्टिकोण, उत्तरदायी रूपरेखा, निवेश परियोजनाओं की समीक्षा सहित एआईआईबी की नीतियों पर विचार करने के लिए बीजिंग, चीन में बैठक की।

(ङ) यूरोपीय संघ के साथ निवेश संरक्षण संधि (आईपीए) पर एक अंतर-सत्रीय दौर डीवीसी के माध्यम से आयोजित किया गया।

(च) डीवीसी के माध्यम से आयोजित भारत-रूस बीआईटी वार्ता का 11 वां दौर।

(छ) ब्रसेल्स में आईपीए पर भारत-यूरोपीय संघ की चौथे दौर की चर्चा।

(ज) भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी)/निवेश अध्याय वार्ता का 8वां दौर नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

(झ) आईएसडीएस सुधारों पर यूएनसीआईटीआरएएल कार्य समूह III का 45 वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया।

(ञ) ईबीआरडी के सतत अवसंरचना समूह की प्रबंधन निदेशक सुश्री नंदिता प्रसाद और ईबीआरडी के कॉर्पोरेट कार्यनीति के प्रबंधन निदेशक श्री कार्लोस सैन बासिलियो के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

(घ) विश्व बैंक के साथ "महामारी त्वरित कार्यक्रम के लिए भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को बदलने" और "भारत के उन्नत स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रम" के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए।

(ङ) विशाखापटनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम - ट्रैन्य 2" के लिए 141.12 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर बातचीत की गई।

(viii) इस महीने के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

(क) आईआईएम कलकत्ता और आईआईएम रायपुर में परियोजना वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(ख) एसपी जैन और आईआईएम शिलांग में परियोजना प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(ग) एनएलएसआईयू बैंगलोर में सरकारी अनुबंध और मुकदमेबाजी प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी के निर्देशों/आदेशों का पालन न करना: शून्य

5. माह के दौरान मंजूर किए गए एफडीआई प्रस्तावों का ब्यौरा और विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

मंजूर किए गए प्रस्तावों की संख्या	:	03
विभाग द्वारा अनुमोदन प्रतीक्षित है।	:	07

(ट) बहुपक्षीय विकास बैंकों/द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तपोषण की मांग करने वाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग जांच समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) की 138वीं बैठक।

(ठ) अपर सचिव (एमबीसी) ने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं, नीतिगत प्राथमिकताओं, एमडी के वैश्विक नीति एजेंडा (जीपीए) और विज्ञप्तियों के सृजन खंडों पर चर्चा करने के लिए आईएमएफसी डिप्टीज की बैठक में भाग लिया।

(vi) इस माह के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गईं:

(क) अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के अवसर पर **75** रुपये मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का।

(ख) श्री नंदमुरी तारक रामा राव की जन्म शताब्दी जयंती के अवसर पर **100** रुपये मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का।

(ग) प्रोजेक्ट टाइगर के **50** वर्ष पूरे होने के अवसर पर **50** रुपये मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का।

(घ) सीबीआई के हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर **60** रुपये मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का।

(vii) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित ऋण/अनुदान समझौतों पर हस्ताक्षर/बातचीत की गई:

(क) वित्त वर्ष 2022-23 ऋण पैकेज के तहत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ओडीए के लिए नोट्स के आदान-प्रदान और ऋण समझौते पर निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं:

- मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना (IV) के लिए जेपीवाई 300 बिलियन (16800 करोड़ रुपये) का ऋण।
- पटना मेट्रो रेल निर्माण परियोजना (1) के लिए जेपीवाई 98.612 बिलियन (लगभग 5509 करोड़ रुपये) का ऋण।
- पश्चिम बंगाल में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया परियोजना के लिए वन और जैव विविधता संरक्षण के लिए जेपीवाई 9.308 बिलियन (लगभग 520 करोड़ रुपये) का ऋण।
- पश्चिम बंगाल में 'जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया के लिए वन और जैव विविधता संरक्षण परियोजना' के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (II) के लिए जेपीवाई 18.894 बिलियन (लगभग 1055.53 करोड़ रुपये) का ऋण।

(ख) केआरडब्ल्यू 215.098 बिलियन (लगभग 1345 करोड़ रुपये) की नागपुर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए ऋण समझौते पर एक्सपोर्ट- इमपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) एएफडी के साथ 'राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास' और 'हिमाचल प्रदेश के पांच शहरों को जल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने' के लिए क्रमशः 160 मिलियन यूरो और 72 मिलियन यूरो की ऋण राशि के लिए दो ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।